भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

10 नवंबर, 2014

धान खरीदी पर सीमा के खिलाफ

किसानों के धान खरीदी पर बोनस न देने एवं प्रति एकड़ 10 क्विंटल धान ही खरीदने की सीमा तय करने की केंद्र एवं छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों की किसान विरोधी नीति का भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कड़ा एतराज जताती है और तमाम किसानों का आह्वान करती है कि वे इसके खिलाफ संगठित व जुझारू आंदोलन करें। दरअसल सरकारों की इस किसान विरोधी कदम के पीछे साम्राज्यवादियों को फायदा पहुंचाने का बहुत बड़ा षड़यंत्र छुपा हुआ है। किसानों से सिर्फ 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा तय करना एवं फसलचक्र परिर्वतन की वकालत करना किसानों के द्वारा धान उत्पादन को हतोत्साहित करने एवं देश को अनाज के लिए साम्राज्यवादियों पर निर्भर करने लायक पराधीन बनाने का देशद्रोही कदम है। फसलचक परिवर्तन के नाम पर रतनजोत जैसे वाणिज्यिक फसलों को प्रोत्साहित करना भी बहुराष्टीय कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली नीति का हिस्सा है। एक ओर अमेरिका, जापान जैसे साम्राज्यवादी देश अपने यहां किसानों को सौ फीसदी रियायतें दे रहे हैं तो दूसरी ओर हमारे देश के किसानों को पहले से मिलने वाली थोड़ी बहुत रिहायतों में कटौती कर रही हैं या पूरी तरह बंद कर रही हैं, यहां की सरकरें। यह देश के किसानों को पंगु बनाने की सरकारी साजिश है। साम्राज्यवादी ताकतों के साथ सांठगांठ करने वाले शोसक–शासक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकरों के इस किसान विरोधी कदम का कड़ा विरोध करने एवं इसके खिलाफ करने हम तमाम प्रगतिशील, जनवादी, व देश भक्त ताकतों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं किसान ,मजदूरों का आव्हान करते हैं। किसानों से धान खरीदी पर लगायी गयी सीमा रद्द करने, धान का समर्थन मूल्य 2500 प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर आंदोलन करने हम छग के किसानों का आव्हान करते हैं और ऐलान करते हैं कि हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष के साथ है।

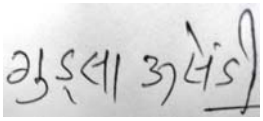

(गुड्सा उसेण्डी)
प्रवक्ता,
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी,
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)